[Shri S. N. Deshmukh]

can even be referred to the Press Council of India. I submit, Sir, if such slander is allowed to be printed, and that too in a box, people will lose faith in democracy. Therefore, this may be looked into and the matter, if possible, may be referred to the Presss Council of India.

THAKUR JAGATPAL SINGH (MADHYA PRADESH): Sir, I support this.

CENTRAL ASSISTANCE TO ORISSA TO MEET THE DROUGHT SITUATION

SHRI BASUDEB MOHAPATRA (Orissa): Sir, serious drought condition is prevailing in the State of Orissa. All the 13 districts have been affected by drought except some irrigated patches. The total cultivable area under irrigation is only 26 per cent. The rest of 74 per cent of and depends on rainfall for good harvest.

The State Government has sought an assistance of Rs. 155 crores from the Centre. The Central team has visited the drought affected area and assessed the situation. But the gravity of the situation can be well imagined from a press report appearing in the "AMRIT BAZAR PATRIKA", date the 26th of August, 1987. Sir, the report says:

> "Mr. M. D. Asthana, leader of the Central team currently visiting the drought-hit areas of Orissa, today assured that the Centre would provide the required financial and foodgrains assistance to the State to meet the situation arising out of the natural calamity.....
>
> "Dr. Asthana, who made an on-the-spot assessment of the drought situation in the western Orissa districts of Kalahandi and Bolangir during the past two days, described the situation there as "very unhappy".

Sir, in view of this, besides demanding Rs. 155 crores in its memorandum, the State Government has requested the Central Government to supply 70,000 tons of rice per month against a supply of 20,600 ton per month at present in order to strengthen the public distribution system in drought affected areas.

Since the Centre has already sanctioned Rs. 250 crores for other drought-hit States, Orissa should get its due share immediately.

The Central Government should make arrangements to provide edible oil and other essential commodities to Orissa in adequate quantity.

Drinking water is a problem in Orissa, specially in backward and tribal areas and also in saline belt. Sufficient amount should be allocated for this purpose.

Liberal Central assistance should be given to Orissa to meet the drought situation immediately.

Thank you.

ALLEGED SALES TAX EVASION BY BIG INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOUSES

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में ऐसा सवाल खड़ा कर रहा हूं जिससे पता चलेगा कि यह सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर, उनके साथ सांठगांठ करके जनता को टेक्स से कितना मार रही है और पूंजीपति कितना मार रहे हैं। इसके लिए बाहर के किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उनकी कम्पनी के अफसरों ने जो चिट्ठी लिखी है उनमें से केवल दो चिटिठयां कोट करना चाहता हूं जिससे आप को पता चल जायेगा कि कितना बड़ा अनर्थ इस देश की जनता के साथ ये पूंजीपति कर रहे हैं। जो टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी जमशेदपुर में है इस की चीजों के दाम तय होते हैं कलकत्ता में लेकिन डायरेक्टर मेटीरियल का कंसाइनमेंट एजेंसी के थ्रू देने से सेंट्रल गवर्नमेंट का सेल्स टेक्स 4 परसेंट और लोकल सरकार का 8 या 10 परसेंट लगता है। मैं आपको पढ़ कर सुना दे रहा हूं। आप रहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है जबकि सरकार जनता का करोड़ों और अरबों रुपय टक्स मार कर

बैठी हुई है। हम सुनते थे कि इंकम टेक्स की ही मार पड़ती है जब यह सेल्स टेक्स भी जनता से लिया जाता है। यह सरकार के लिए चुनौती है। मैं केवल एक पूंजीपति का नाम कोट करना चाहता हूं...

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच हनुमनतप्पा) : नाम नहीं कोट करना है।

श्री राम अवधेश सिंह : नाम को कोट करना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : इसे छोड़ दीजिए। उस कम्पनी का नाम ले लीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं। 16 फरवरी, 1983 को लिखी गयी है। डायरेक्टर आफ एकाउंटंट् ने लिखी है डायरेक्टर, मेटीरियल, कलकत्ता को। उसमें लिखा है...

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : वह लेटर भेज दीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : सिर्फ दो लाइन पढ़ता हूं। वह इस प्रकार है:

"Delivery of 1300 M.T. scrap to M|s Technico Allows and Steel Trading Co. through their consignment agencies at Calcutta & Delhi.

"We wish to bring to your notice that the transaction to be made as per the above sanction is a clear case of "pre-determined sale" and would attract Central Sales Tax, which has not been envisaged. Although we have already agreed to sell the scrap to the above party yet the material is being moved from Jamshedpur as a consignment transfer.

"This would not be in conformity with the Sales Tax laws.

We, therefore, feel that to avoid legal complications on subsequent detection by the commercial taxes authorities, the material should be sold from Jamshedpur charging the extra Rs. 105 per tonne which the company is to gain as a sale from stockyard. This can be done since scrap is not a JPC item. The party can be charged 4 per cent Central Tax on their giving a declaration so that there would be no extra liability to them on this score also.

However, if due to some genuine difficulties, the above cannot be followed we suggest that for transfer of material and subsequent sale thereof, the documents should be raised in proper sequence so as to avoid complications."

इससे बढ़कर चोरी की बात और क्या हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि खुद चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं उनको देखकर इसको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता है। दूसरी चिट्ठी भी मेरे पास है। उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आप चिट्ठी उनके पास भेज दीजिये।

श्री राम अवधेश सिंह : श्रीमन्, यह दूसरी चिट्ठी है। इसको मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो यह अन्याय होगा; भारत की जनता के साथ अन्याय होगा। देश की जनता की आवाज बन कर मैं यहां पर आया हूं। इसलिये अगर कहीं पर चोरी होती है तो सरकार को बताना हमारा फर्ज है।

As least let me read five lines. Heaven is not going to fall.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): If you don't read also, heaven will not fall. Why don't you pass it on to the Minister?

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : श्री राम अवधेश सिंह : यह स्पेशल मेंशन का तरीका नहीं है। अब आप बैठ जाइये... (**व्यवधान**)।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, अब इसका नम्बर पढ़ देता हूं।

(श्री राम अवधेश सिंह)

"No. SP/Misc./2387 dated 13-12-83. Sub: Delivery of materials.

As agreed by Vice-President (Commercial), the materials against the following lots purchased by their above two parties will be delivered through their consignment agencies at Calcutta and Delhi. In other words, the subject materials covering the following lots will be for all practical purposes sold through stockyard consignment agencies.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You wil have to stop. I will call the next man.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: "We are, therefore, taking out the subject materials covering the following lots out of the Auction list. This is for your information and necessary action."

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत सीरियस मामला है.... (व्यवधान) कहां पर कितनी रकम है, यह सब लिखा हुआ है। यह लेटर मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। इसमें पांच करोड़ रूपयों का टैक्स का घपला है। एक पार्टी हरियाणा की है। जो निगम है, जो फर्म है, उसका नाम मैं पढ़ देता हूं.... (व्यवधान)।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : अब आप बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें पांच करोड़ रुपयों का खपला हुआ है जो 17 पार्टियों के टिस्को के कैंसाइमेंट के जो एजेन्टस हैं उनके जरिए देश के करोड़ों रुपये मारे गये हैं। यह टैक्स की चोरी हुई है। यह चनौती है फाइनेन्स मिनिस्टर के लिए क्लीन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी के लिए.... (व्यवधान)। यह तो मैं आपका काम कर रहा हूं। जिन लोगों ने चोरी की है उनके बारे में बता रहा हूं। इससे आपकी छवि अच्छी होगी .... (व्यवधान)

मैं इस बात का चार्ज कर रहा हूं। आपको तो ऐसे अच्छी बात का समर्थन करना चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। आप लोग जब कहते हैं तो इस तरह क्यों करते हैं। (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You have no right to encroach upon the time of the other Members.

NEED FOR REMISSION OF STUDENTS' FEES AND WAIVING OF INTEREST ON PEASANTS' LOANS IN DROUGHT AFFECTED AREAS

श्री शांति त्यागी : (उत्तर प्रदेश) : महोदय, देश के एक बहुत बड़े हिस्से में सूखा पड़ने से बहुत क्षति हुई है। इस पर आपने, इस माननीय सदन और दूसरे माननीय सदन ने तथा हमारी सरकार ने अपनी चिंता प्रकट की है। श्रीमन्, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वे देश में किसी भी सूरत में भुखमरी नहीं फैलने देंगे और किसी भी स्त्री-पुरुष को भूखों नहीं मरने देंगे। इस दिशा में उन्होंने यह भी घोषणा की है कि राहत का काम और सूखे से लड़ने का काम वार-फुटिंग पर किया जायेगा। श्रीमन्, इस दिशा में हमारी सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। महोदय, हमारे देश के कई प्रांतों में सूखे और बाढ़ से बड़ी विनाशलीला हुई है यह आप जानते हैं और पूरे देश को इसका बड़ा अफसोस है। मान्यवर, जिन राज्यों में सूखा पड़ा है वहां के ग्रामीण अंचलों से यह मांग की जा रही है कि उस क्षेत्र के स्कूल और कालेजों में जो ग्रामीण बच्चे पढ़ते हैं, उन सूखाग्रस्त राज्यों में कालेज या स्कूलों के विद्यार्थियों की इस एकेडेमिक सेशन की, इस वर्ष की फीस माफ कर दी जाय। यह खाली विद्यार्थियों की मांग नहीं है। बहुत से किसान संगठनों और कुछ राजनैतिक पार्टियों ने भी इस बात की मांग की है। अतः मेरा आग्रह है कि इस बात को स्वीकार किया जाय। श्रीमन्, यह भी मांग की जा रही है कि किसानों, सीमांत किसानों और देहात के गरीबों के ऊपर जो सरकारी कर्जा है, माफ किया जाय। माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर हैं, वे शायद इस बात पर एतराज करें कि यह ठीक नहीं। अलबत्ता इन गरीबों की इमदाद करनी आवश्यक है और अगर कोई मौजूदा कानून उसके रास्ते में रुकावट डालता है तो उस कानून को तब्दील कर किया जाय और जो गरीब लोग हैं उनको इमदाद दी जाय। मैं आप से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता